भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1843

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी ऊर्जा उपकरण विनिर्माता

†1843. श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में उत्पादन इकाइयों वाली चार विदेशी ऊर्जा उपकरण विनिर्माता कंपनियों को सरकारी ऊर्जा पारेषण निविदाओं में भाग लेने के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा इन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं कि ऐसी कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला की अनुकूलता और खरीद के मानकों से कोई समझौता किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस छूट से भारत के विद्युत पारेषण तंत्र के विस्तार में किस प्रकार से सहायता मिलेगी और यह देश की बढ़ती विद्युत अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी किस प्रकार सहायक होगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : सरकार ने हाल ही में भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों के व्यापक स्वामित्व वाली 4 कंपनियों को विद्युत परियोजनाओं के लिए खरीद बोलियों में भाग लेने की अनुमति दी है। यह अनुमति ऐसी संस्थाओं द्वारा निर्धारित घरेलू सामग्री संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के अध्यधीन दिनांक 24.06.2026 से दो वर्ष की अवधि के लिए दी गई है:

(i) मेसर्स टीबीईए एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
(ii) मेसर्स नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
(iii) मेसर्स न्यू नॉर्थईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
(iv) मेसर्स ताईकाई इलेक्ट्रिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।

(ग) और (घ) : भारत में मौजूद ऐसी कंपनियों में बनने वाले उत्पादों को निर्धारित प्रमाणन एजेंसियों द्वारा भारतीय मानकों के अनुसार अनिवार्य परीक्षणों और प्रमाणीकरण से गुज़रना होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और साथ ही प्रतिस्पर्धी खरीद को आसान बनाने के लिए, ज़रूरी साइबर सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने सहित पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और आपूर्ति बाधाएं दूर होंगी, साथ ही 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के उद्देश्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

****